(ख) इस परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है और वर्तमान में इस नहर परियोजना के अन्तर्गत कितने हेक्टर भूमि में सिंचाई की जा रही है ; और

(ग) क्या सरकार ने 1993-94 और 1994-95 में इस परियोजना के लिए राज्य सरकार को कोई राशि दी है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) से (ग) 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार उत्तर कोयल नहर परियोजना की भौतिक प्रगति, सिंचाई क्षमता और वित्तीय स्थिति इस प्रकार है :—

घटक	पूरा किया गया कार्य
भौतिक	
1. कुटकु बांध . .	93%
2. द्वार का निर्माण . .	80%
3. मोहम्मद गंज बराज . .	99%
4. बराज पर पुल . .	शून्य
5. मुख्य नहर	
(क) बायां तट नहर .	8%
(ख) पक्का करने का कार्य	शून्य
(ग) दायां तट नहर . .	97%
(घ) पक्का करने का कार्य	79%
6. **वितरण प्रणाली**	
(क) मिट्टी कार्य . .	34%
(ख) पक्का करने का कार्य	22%
(ग) जल निकास . .	9%

सिंचाई क्षमता : 104.72 हजार हेक्टेयर की कुल सिंचाई क्षमता की तुलना में 33.06 हजार हेक्टेयर क्षमता का सृजन किया गया है और लगभग 20.00 हजार हेक्टेयर का उपयोग किया जा रहा है।

वित्तीय : इस परियोजना की अनुमानित लागत 475 करोड़ रुपये है। जून, 1994 तक 361.37 करोड रुपए का व्यय किया गया है। योजना आयोग के कार्य दल ने वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिए परिव्ययों की सिफारिश की है जो इस प्रकार है :—

वर्ष	प्रावधान (करोड़ रुपए)	व्यय (करोड़ रुपए)
1993-94	22.00	11.32
1994-95	17.00	2.21 (जून, 1994 तक)

वर्तमान नीति के अनुसार, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, प्रतिपादन, क्रियान्वयन तथा वित्त पोषण स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र एक मुश्त अनुदान तथा ऋण देता है जो किसी क्षेत्र से जुड़ा नहीं होता है।

National Institute for Research and Training in the Field of Ground Water

2945. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA :

SHRI ANANT RAM JAISWAL: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct a National Institute for Research and Training in the field or ground water in the country;

(b) if so, the objectives in setting up such an Institutes;

(c) whether any survey has been made to identify the areas ; and

(d) if so, what are the details thereof, stating the estimated cost likely to be incurred thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON : (a) Yes, sir;

(b) The objectives of the Institute are to create facilities for training national and international professionals and sub-professionals at the induction, mid-career, senior and management levels in all relevant aspects of ground water investigation, exploration, assessment, planning, development, management, conservation and protection.

(c) and (d) After taking into consideration the recommendations of the Site Selection Committee and other relevant factors, the Government have decided to set up the Institute at Raipur. The revised estimated cost for establishing the Institute is Rs. 832.00 lakhs.